



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218990  
CG-DL-E-01042020-218990

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]  
No. 84]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

**विषय:** बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

1. पृष्ठभूमि

सं. W-28/1/2019-आईपीएचडब्ल्यू- एमईआईटीवाई.—1.1 इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का प्रतिस्पर्धी (क्रॉस-कटिंग) आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पिछले 4 वर्षों के दौरान लगभग 25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ तेजी से बढ़ा है। हालांकि, यह विकास के लिए वास्तविक क्षमता की तुलना में कम है, जो कि बड़े पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव जैसी विशिष्ट बाधाओं से प्रभावित होता है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और अन्य देशों में प्रस्तावित किए गए प्रोत्साहनों के समान प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

1.2 वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2012 में लगभग 1.3% से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.0% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में ₹1,90,366

- करोड़ (29 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹4,58,00,000 करोड़ (70 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के लिए मांग में तेजी से वृद्धि अर्थात् वर्ष 2025 तक लगभग 400 अरब अमरीकी डालर (लगभग ₹26, 00,000 करोड़) होने की उम्मीद के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिकी के मद में आयात के कारण तेजी से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को वहन नहीं कर सकता है।
- 1.3 अन्य योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए अपेक्षित सीमित राहत के बावजूद, अन्य बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की इन कमियों को दूर करने के लिए एक मेकेनिज्म की जरूरत है।
- 1.4 उभरते हुए अवसरों के साथ समान स्तर: इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों के साथ असमान स्तर की कमी का सामना करना पड़ता है। उद्योग (आईसीईए और एलीसिना) के अनुमान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त अवसंरचना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद; वित्त की उच्च लागत; गुणवत्तायुक्त विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता; सीमित डिजाइन क्षमताओं की कमी और उद्योगों के द्वारा अनुसंधान और विकास पर कम ध्यान केंद्रित करने के कारण लगभग 8.5% से 11% की कमी से जूझ रहा है।
- 1.5 इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई 2019) : एनपीई 2019 का लक्ष्य चिपसेट सहित मुख्य संघटकों को विकसित करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योगों के लिए सक्षम वातावरण बनाने हेतु देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन एंड विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है।
2. उद्देश्य : बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।
3. प्रोत्साहन की मात्रा : इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों को यथा परिभाषित आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए पैरा 7 में यथापरिभाषित भारत में विनिर्मित और लक्षित खंडों में शामिल वस्तुओं की उत्तरोत्तर बढ़ती बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
4. लक्षित खंड : यह योजना केवल लक्ष्य खंडों यानी मोबाइल फोन और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के लिए लागू होगी (जैसा कि अनुबंध-ख में विस्तार से दिया गया है)।
5. पात्रता : योजना के तहत सहायता केवल भारत में लक्षित खंडों के निर्माण में लगी कंपनियों को ही प्रदान की जाएगी। इसमें एफडीआई नीति परिपत्र 2017 में यथापरिभाषित अनुबंधित विनिर्माता शामिल होंगे।
- 5.1 प्रत्येक आवेदन लक्ष्य खंडों में से एक (1) तक ही सीमित होगा।
- 5.2 पात्रता बढ़े हुए निवेश और निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (जैसा कि व्यापार के सामान से अलग है) की सीमा के अधीन होगी। एक आवेदक को प्रोत्साहन के संवितरण के लिए पात्र होने के लिए सभी सीमा शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अर्हता सीमा मानदंड अनुबंध-क में विस्तार से दिए गए हैं।

- 5.3 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता किसी अन्य योजना के तहत पात्रता और विलोमतः को प्रभावित नहीं करेगी।
6. **योजना का कार्यकाल:** योजना के तहत सहायता आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी जैसा कि पैरा 7 में परिभाषित किया गया है।
- 6.1 यह योजना आवेदन प्राप्त करने के लिए शुरू में 4 महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है।
- 6.2 उद्योग से प्रतिक्रिया के आधार पर योजना को किसी भी समय आवेदन के लिए फिर से खोला जा सकता है।
- 6.2.1 आरंभिक आवेदन की अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए आवेदक केवल योजना के शेष कार्यकाल के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे।
7. **आधार वर्ष:** उत्तरोत्तर निवेश की गणना और निर्मित माल (व्यापार के सामान से अलग) की उत्तरोत्तर बिक्री के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा।
8. **प्रोत्साहन परिव्यय**
- 8.1 **कुल प्रोत्साहन:** योजना के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रोत्साहन परिव्यय और संचयी प्रोत्साहन परिव्यय इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कुल प्रोत्साहन
	₹ करोड़ रु
वर्ष 1	5334
वर्ष 2	8064
वर्ष 3	8425
वर्ष 4	11,488
वर्ष 5	7640
<b>कुल</b>	<b>40,951</b>

- 8.2 **प्रति कंपनी प्रोत्साहन:** अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय की गई सीलिंग के आधार पर आधार वर्ष से प्रति कंपनी प्रोत्साहन विनिर्मित माल (ट्रेडेड माल से अलग) की उत्तरोत्तर बिक्री पर लागू होगा।
9. **संगणना का आधार**
- 9.1 विभागों और मंत्रालयों/एजेंसियों और सांविधिक लेखापरीक्षक के संलग्न प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर उत्तरोत्तर निवेश और निर्मित वस्तुओं की बिक्री का आकलन किया जाएगा।
- 9.2 संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से एमईआईटीवाई द्वारा कार्यात्मक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

### अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया

- 10.1 योजना के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है।
- 10.2 सभी पहलुओं में पूर्ण एक प्रारंभिक आवेदन नियत तारीख से पहले जमा करना होगा। आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद पावती जारी की जाएगी। पावती को पीएलआई योजना के तहत अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाएगा।
- 10.3 पात्र आवेदनों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।
- 10.4 ऐसे पात्र आवेदकों को प्रोत्साहन जारी किया जाएगा, जो आवश्यक श्रेसहोल्ड को पूरा कर रहे हैं और जिनके संवितरण दावे सही पाए जाते हैं।
- 10.5 योजना के तहत प्रोत्साहन 01.08.2020 से लागू होगा।

### 11. नोडल एजेंसी

- 11.1 यह योजना एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू की जाएगी।
- 11.2 इस तरह की नोडल एजेंसी एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपे गए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। पीएमए के विस्तृत गठन, कामकाज और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी योजना संबंधी दिशानिर्देशों में दी जाएगी।
- 11.3 पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए पीएमए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:
  - 11.3.1 योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदनों का मूल्यांकन और पात्रता का सत्यापन
  - 11.3.2 योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण के लिए योग्य दावों की जांच
  - 11.3.3 योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में आंकड़ों का संकलन जिसमें स्कीम के तहत कंपनियों के लिए निर्मित सामानों की वृद्धि और निवेश की बिक्री शामिल है।

### 12. अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)

- 12.1 सी ई ओ, नीति आयोग, सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय, सचिव व्यय विभाग, सचिव, एमईआईटीवाई, सचिव राजस्व विभाग, सचिव डीपीआईआईटी और डीजीएफटी को शामिल करते हुए एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की जाएगी।
- 12.2 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) अनुमोदन के लिए योजना के तहत परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा पात्र पाए आवेदनों पर विचार करेगी।

- 12.3 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संवितरण के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा जांच और सिफारिश किए गए दावों पर विचार करेगी।
- 12.4 अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) योजना के तहत पात्र कंपनियों की उनके निवेश, रोजगार सृजन, उत्पादन और मूल्यवर्धन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करेगी।
- 12.5 योजना के कार्यकाल के दौरान अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा प्रोत्साहन की दरों, सीमाओं, लक्षित खंडों और पात्रता मानदंड को संशोधित किया जा सकता है।
- 12.6 योजना दिशानिर्देशों में कोई संशोधन करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भी अधिकृत किया जाएगा।
- 12.7 योजना के दिशानिर्देशों में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के विस्तृत गठन, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

पात्रता थ्रेसहोल्ड मानदंड

खंड	प्रस्तावित प्रोत्साहन दर	आधार वर्ष से उत्तरोत्तर निवेश	आधार वर्ष से विनिर्मित वस्तुओं की उत्तरोत्तर बिक्री
मोबाइल फोन (चालान का मूल्य ₹15,000 और अधिक)*	वर्ष 1: 6% वर्ष 2: 6% वर्ष 3: 5% वर्ष 4: 5% वर्ष 5: 4%	₹1,000 करोड़ 4 वर्ष से अधिक संचयी न्यूनतम (करोड़): वर्ष 1: 250 वर्ष 2: 500 वर्ष 3: 750 वर्ष 4: 1,000	वर्ष 1: ₹4,000 करोड़ वर्ष 2: ₹8,000 करोड़ वर्ष 3: ₹15,000 करोड़ वर्ष 4: ₹20,000 करोड़ वर्ष 5: ₹25,000 करोड़
मोबाइल फोन (घरेलू कंपनियों) **		₹200 करोड़ 4 वर्ष से अधिक संचयी न्यूनतम (करोड़): वर्ष 1: 50 वर्ष 2: 100 वर्ष 3: 150 वर्ष 4: 200	वर्ष 1: ₹500 करोड़ वर्ष 2: ₹1,000 करोड़ वर्ष 3: ₹2,000 करोड़ वर्ष 4: ₹3,500 करोड़ वर्ष 5: ₹5,000 करोड़
निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक (अनुबंध-ख में विस्तार से दिए अनुसार)		₹100 करोड़ 4 वर्ष से अधिक	वर्ष 1: ₹100 करोड़ वर्ष 2: ₹200 करोड़ वर्ष 3: ₹300 करोड़ वर्ष 4: ₹450 करोड़

खंड	प्रस्तावित प्रोत्साहन दर	आधार वर्ष से उत्तरोत्तर निवेश	आधार वर्ष से विनिर्मित वस्तुओं की उत्तरोत्तर बिक्री
		संचयी न्यूनतम (करोड़): वर्ष 1: 25 वर्ष 2: 50 वर्ष 3: 75 वर्ष 4: 100	वर्ष 5: ₹600 करोड़

\*पात्रता के लिए, चालान मूल्य पर ध्यान दिए बिना, निर्मित वस्तुओं की सभी उत्तरोत्तर बिक्री (लक्षित खंडों के तहत शामिल) पर विचार किया जाएगा।

\*\*घरेलू कंपनियों को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो वर्ष 2017 के एफडीआई के नीतिगत परिपत्र में परिभाषित भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में हैं। किसी भी कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों के 'स्वामित्व' वाली कंपनी के रूप में तब माना जाता है जब इसमें 50% से अधिक पूंजी किसी निवासी भारतीय नागरिकों और/या भारतीय कंपनियों के पास होती है, जो अंततः किसी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में होती हैं।

**अनुबंध-ख**

पीएलआई योजना के तहत पात्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सूची

क्र.सं.	माल (वस्तुओं) का विवरण
1.	एसएमटी संघटक
2.	ट्रांजिस्टर, डायोड, थाइरिस्टर आदि सहित डिस्क्रीट अर्धचालक उपकरण ।
3.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए प्रतिरोधक, कैपेसिटर आदि सहित निष्क्रिय संघटक ।
4.	मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पीसीबी लेमिनेट, प्रीप्रेज, फोटोपोलिमर फिल्में, पीसीबी मुद्रण स्याही ।
5.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए सेंसर, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर, क्रिस्टल ।
6.	पैकेज में प्रणाली (एसआईपी) ।
7.	माइक्रो/नैनो-इलेक्ट्रॉनिक संघटक जैसे माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स (एमईएमएस) और नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स (एनईएमएस) ।
8.	असेंबली, परीक्षण, मार्क आईएनजी और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयां ।

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

(IPHW DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2020

**Subject:** Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing**1. Background**

**No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY.**—1.1. Electronics permeate all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. In India, electronics manufacturing has grown rapidly with a CAGR of around 25% during the last 4 years. However, this pales in comparison to the actual potential for growth which is curtailed by specific constraints such as large capital investments and rapid changes in technology. The Government has been actively working to create a conducive environment for manufacturing and to offer incentives comparable with those offered in other countries to attract large investments into the manufacturing sector.

- 1.2. India's share in global electronics manufacturing has grown from 1.3% in 2012 to 3.0% in 2018. The domestic production of electronics hardware has increased substantially from INR 1,90,366 crore (USD 29 billion) in 2014-15 to INR 4,58,006 Crore (USD 70 billion) in 2018-19. With the domestic demand for electronics hardware expected to rise rapidly to approximately INR 26, 00,000 crore (USD 400 billion) by 2025, India cannot afford to bear the rapidly increasing foreign exchange outgo on account of import of electronics.
  - 1.3. Given the limited relief expected for the electronics manufacturing sector under other schemes, there is need for a mechanism to compensate for the manufacturing disabilities vis-à-vis other major manufacturing economies.
  - 1.4. **Level playing field with emerging opportunities:** The electronics hardware manufacturing sector faces the lack of a level playing field vis-à-vis competing nations. As per industry estimate (ICEA and ELCINA), electronics manufacturing sector suffers from a disability of around 8.5% to 11% on account of lack of adequate infrastructure, domestic supply chain and logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; limited design capabilities and focus on R&D by the industry; and inadequacies in skill development.
  - 1.5. **National policy on electronics (NPE 2019):** The vision of NPE 2019 is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally.
2. **Objective:** The Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investments in the electronics value chain including electronic components and semiconductor packaging.
  3. **Quantum of Incentive:** The Scheme shall extend an **incentive of 4% to 6% on incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under target segments**, to eligible companies, **for a period of five (5) years subsequent to the base year** as defined in Para 7.
  4. **Target Segments:** The Scheme shall only be applicable for **target segments namely mobile phones and specified electronic components** (as detailed in *Annexure B*).
  5. **Eligibility:** Support under the Scheme **shall be provided only to companies engaged in manufacturing of target segments in India**. This shall include contract manufacturers as defined in the FDI Policy Circular of 2017.
    - 5.1. Each application shall be limited to one (1) of the target segments.

- 5.2. Eligibility shall be subject to thresholds of incremental investment and incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods). An applicant must meet all the threshold conditions to be eligible for disbursement of incentive. Eligibility threshold criteria are detailed in *Annexure A*.
- 5.3. Eligibility under Production Linked Incentive scheme shall not affect eligibility under any other Scheme and vice-versa.
6. **Tenure of the Scheme:** Support under the Scheme shall be provided for a **period of five (5) years subsequent to the base year as defined in Para 7.**
- 6.1. The Scheme shall be open for applications for a period of 4 months initially which may be extended.
- 6.2. The Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the industry.
- 6.3. For applications received post the initial application period, applicants shall only be eligible for incentives for the remainder of the Scheme's tenure.
7. **Base Year: Financial Year 2019-20 shall be treated as the base year** for computation of incremental investment and incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods).

## 8. Incentive Outlay

**8.1 Total Incentive:** The expected annual incentive outlay and cumulative incentive outlay under the Scheme is as follows:

Financial Year	Total Incentive
	<i>INR Crore</i>
Year 1	5,334
Year 2	8,064
Year 3	8,425
Year 4	11,488
Year 5	7,640
<b>Total</b>	<b>40,951</b>

- 8.2. **Incentive Per Company:** The incentive per company will be applicable on incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods) over base year **subject to ceilings** as decided by the Empowered Committee.
9. **Basis of Computation**
- 9.1. Assessment of incremental investment and sales of manufactured goods shall be based on details furnished to the Departments / Ministries / Agencies and Statutory Auditor certificates.
- 9.2. Functional Guidelines will be issued by MeitY in consultation with concerned Departments / Ministries.
10. **Approval and Disbursement Process**
- 10.1. Application under the Scheme can be made by any company registered in India.
- 10.2. An initial application, complete in all aspects, will have to be submitted before the due date. Acknowledgement will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgement shall not be construed as approval under PLI Scheme.

- 10.3. Eligible applications will be appraised on an ongoing basis and considered for approval.
- 10.4. Incentive shall be released to eligible applicants, meeting the required thresholds and whose disbursement claims are found to be in order.
- 10.5. Incentives under the Scheme will be applicable from 01.08.2020.

#### 11. Nodal Agency

- 11.1. The Scheme shall be implemented through a Nodal Agency.
- 11.2. Such Nodal Agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines.
- 11.3. For carrying out activities related to the implementation of PLI Scheme, PMA would inter-alia be responsible for:
- 11.3.1. Appraisal of applications and verification of eligibility for support under the Scheme
- 11.3.2. Examination of claims eligible for disbursement of incentive under the Scheme
- 11.3.3. Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme including Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured goods for companies under the Scheme.

#### 12. Empowered Committee (EC)

- 12.1. An Empowered Committee (EC) including CEO NITI Aayog, Secretary Economic Affairs, Secretary Expenditure, Secretary MeitY, Secretary Revenue, Secretary DPIIT and DGFT will be formed.
- 12.2. The EC will consider applications, as found eligible by the Project Management Agency under the Scheme, for approval.
- 12.3. The EC will consider claims, as examined and recommended by the Project Management Agency, for disbursement as per the laid down procedure.
- 12.4. The EC will conduct a periodic review of eligible companies with respect to their investments, employment generation, production and value addition under the Scheme.
- 12.5. The EC may revise incentive rates, ceilings, target segments and eligibility criteria as deemed appropriate during the tenure of the Scheme.
- 12.6. The EC will also be authorized to carry out any amendments in the Scheme Guidelines.
- 12.7. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the EC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

#### ANNEXURE A

#### Eligibility Threshold Criteria

Segment	Proposed Incentive Rate	Incremental Investment over Base Year	Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year
Mobile Phones (Invoice value of INR 15,000 and above) *	Year 1: 6% Year 2: 6% Year 3: 5% Year 4: 5% Year 5: 4%	INR 1,000 Crore over 4 Years  Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 250 Year 2: 500 Year 3: 750 Year 4: 1,000	Year 1: INR 4,000 Crore Year 2: INR 8,000 Crore Year 3: INR 15,000 Crore Year 4: INR 20,000 Crore Year 5: INR 25,000 Crore

Segment	Proposed Incentive Rate	Incremental Investment over Base Year	Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year
Mobile Phones (Domestic Companies) **		INR 200 Crore over 4 Years  Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 50 Year 2: 100 Year 3: 150 Year 4: 200	Year 1: INR 500 Crore Year 2: INR 1,000 Crore Year 3: INR 2,000 Crore Year 4: INR 3,500 Crore Year 5: INR 5,000 Crore
Specified Electronic Components (detailed in <i>Annexure B</i> )		INR 100 Crore over 4 Years  Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 25 Year 2: 50 Year 3: 75 Year 4: 100	Year 1: INR 100 Crore Year 2: INR 200 Crore Year 3: INR 300 Crore Year 4: INR 450 Crore Year 5: INR 600 Crore

**\*For eligibility all Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under target segments) irrespective of Invoice Value shall be considered.**

**\*\*Domestic Companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Policy Circular of 2017. A company is considered as 'Owned' by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.**

#### **ANNEXURE B**

#### **List of Specified Electronic Components eligible under PLI Scheme**

Sl. No.	Description of Goods
1.	SMT components
2.	Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, thyristors, etc.
3.	Passive components including resistors, capacitors, etc. for electronic applications
4.	Printed Circuit Boards (PCB), PCB laminates, prepregs, photopolymer films, PCB printing inks
5.	Sensors, transducers, actuators, crystals for electronic applications
6.	System in Package (SIP)
7.	Micro / Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
8.	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

**File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part(1)**  
**Government of India**  
**Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)**  
**IPHW Division**

**Dated: 11<sup>th</sup> March, 2021**

**Addendum**

**Amendments in Guidelines of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing**

References:

- i. *PLI Scheme Notification No. CG-DL-E-01042020-218990 dated 1<sup>st</sup> April, 2020 in Part – I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) [F.No. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*
- ii. *Guidelines for the Operation of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 1<sup>st</sup> June, 2020 [F.No. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) notified the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing on April 01, 2020. Subsequently, Guidelines for the operation of the Scheme were notified on 01.06.2020. The First Round of the Scheme was open for receiving applications till 31.07.2020.

2. As per Para 12.6 of the PLI Scheme, *the EC will also be authorized to carry out any amendments in the Scheme Guidelines*. Therefore, in accordance with Para 12.6 of the Scheme, the EC in its meeting held on 11<sup>th</sup> February 2021 has approved the following amendment in the PLI Scheme Guidelines:

Para	Existing Para	Amended Para
2.12	<b>Net Sales Turnover:</b> Net Sales Turnover shall mean the Gross Sale Turnover net of credit notes (raised for any purpose), discounts (including but not limited to cash, volume, turnover, target or for any other purpose) and taxes applicable.	<b>Net Sales:</b> Gross Sales net of credit notes (raised for any purpose), discounts (including but not limited to cash, volume, turnover, target or for any other purpose), taxes applicable and <u>expenses pertaining to advertisement and sales promotion, and brand royalty.</u>

**Expenses Pertaining to Advertisement and Sales Promotion:** For the purpose of computing Net Sales, expenses pertaining to advertisement and sales promotion shall be deducted from the Net Domestic Sales proportionately in the ratio of *Total Expenses (pertaining to advertisement and sales promotion) to Total Domestic Revenue of the Applicant Company.*

**Expenses Pertaining to Brand Royalty:** For the purpose of computing Net Sales, expenses pertaining to brand royalty shall be deducted from the Net Sales (for which such royalty expenses have been incurred) proportionately in the ratio of *Total Expenses (pertaining to brand royalty) to Total Revenue (for which such royalty expenses have been incurred).*

3. Accordingly, the definition of *Incremental Sales* mentioned in Para 2.17 may be read as follows:

Para	Existing Para	Amended Para
2.17	<b>Incremental Sales of Manufactured Goods:</b> Sales of Manufactured Goods over a given period minus the Sales of Manufactured Goods in the Base Year over the corresponding period.	<b>Incremental Sales of Manufactured Goods:</b> Net Sales of Manufactured Goods over a given period minus the Net Sales of Manufactured Goods in the Base Year over the corresponding period.

In Para 7.2.3 and Para 10, "Sales of Manufacturing Goods" may be read as "Net Sales of Manufactured Goods"

4. Further, Empowered Committee in its earlier meetings held on 20.08.2020 and 02.10.2020 approved the following amendments:

4.1 **Baseline for Approved Applicants:** The baseline for Sales of Manufactured Goods for an applicant company, for the purpose of the Scheme, shall include sale of goods in the target segment / category in India, in the base year, of the applicant company as well as any entity (group company) whose manufacturing revenue in India has been considered for determining qualification of the applicant company as per Para 3.2 of these Guidelines. *(EC Meeting held on 20.08.2020)*

4.2 The definition of Competent Authority as mentioned in Para 2.24 may be read as follows:

**Competent Authority:** *Competent Authority under the Scheme shall be defined as per delegation of powers for appraisal and approval of Public Funded Schemes and Projects vide OM No. 24(35)/PF-II/2012 dated 05.08.2016 issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance or any subsequent modifications thereof. (EC Meeting held on 02.10.2020)*

5. The PLI Scheme Guidelines issued on 01.06.2020 shall be read incorporating the above changes wherever applicable.

6. This issues with the approval of Hon'ble Minister for Electronics and Information and Technology.



(Saurabh Gaur)

Joint Secretary to the Government of India

Tel No. 011-24363071

Email: [saurabh.gaur@meity.gov.in](mailto:saurabh.gaur@meity.gov.in)

**File No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY**  
**Government of India**  
**Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)**  
**IPHW Division**

**Dated:** June 1, 2020

**Subject: Guidelines for the Operation of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing**

## **1. Background**

- 1.1.** The Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing (hereinafter referred to as ‘Scheme’) has been notified vide notification No. CG-DL-E-01042020-218990 dated 01.04.2020.
- 1.2.** As per Para 6.1 of the Scheme, PLI will be open for receiving applications for four months from the date of notification. Since, the notification was published on 01-04-2020, applications will be received upto 31-07-2020.
- 1.3.** In pursuance of Para 9.2 of said notification and for the effective operation and smooth implementation of the Scheme, the following guidelines are being laid down that have to be read along with the scheme. In case of any inconsistency between the scheme and the guidelines, the provisions of the scheme shall prevail.
- 1.4.** These guidelines have been prepared after detailed consultations with industry and other relevant stakeholders. The Scheme Guidelines inter-alia cover the following:
  - 1.4.1. Definitions
  - 1.4.2. Qualification and Eligibility
  - 1.4.3. Application and Online Portal

1.4.4. Project Management Agency (PMA) and Empowered Committee (EC)

1.4.5. Approval under PLI and Determination of Baseline

1.4.6. Calculation and Disbursement of Incentives

## 2. Definitions

**2.1. Target Segments:** In accordance with Para 4 of the Scheme, Target Segments shall mean two segments viz. Mobile phones and Specified Electronic Components as in Annexure B in the Scheme.

**2.2. Applicant:** Applicant for the purpose of the Scheme is a company registered in India, proposing to manufacture goods covered under Target Segments, and making an application for seeking approval under the Scheme. The applicant can operate new or existing manufacturing facility(ies) to manufacture goods covered under the Target Segments. The aforesaid manufacturing can be carried out at one or more locations in India.

**2.3. Application:** Application submitted by an applicant to MeitY / Project Management Agency (PMA) as per the Application Form prescribed at Annexure 3 of these Guidelines containing requisite information, along with supporting documents and application fee.

**2.4. Application Window:** Time period allowed for filing of applications. In accordance with Para 6.1 of the Scheme, the Application Window shall be 4 months from the date of notification of the Scheme initially and may be extended and / or reopened based on response from the industry.

**2.5. Application Acknowledgement Date:** The date on which an application is acknowledged by MeitY / Project Management Agency (PMA) after carrying out initial scrutiny in this regard.

- 2.6. Application Approval Date:** The date on which, based on an application, approval under the Scheme is issued by the Project Management Agency (PMA).
- 2.7. Project Management Agency (PMA):** Refers to the Financial Institution(s) or any other authority(ies) appointed by MeitY to act on its behalf for receipt and appraisal of applications, determination of baselines, verification of eligibility and examination of disbursement claims through any method / document deemed appropriate and for managing the above-mentioned in accordance with these Guidelines.
- 2.8. Empowered Committee (EC):** A Committee consisting of CEO NITI Aayog, Secretary Economic Affairs, Secretary Expenditure, Secretary MeitY, Secretary Revenue, Secretary DPIIT and DGFT that has been formed in accordance with Para 12.1 of the Scheme.
- 2.9. Investment:** “Investment” as mentioned in Para 5.2 of the Scheme shall mean:
- 2.9.1. Expenditure incurred on Plant, Machinery, Equipment and Associated Utilities: This shall include expenditure on plant, machinery, equipment and associated utilities as well as tools, dies, moulds, jigs, fixtures (including parts, accessories, components, and spares thereof) of the same, used in the design, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of any of the goods covered under Target Segments. It shall also include expenditure on packaging, freight / transport, insurance, and erection and commissioning of the plant, machinery, equipment, and associated utilities. Associated utilities would include captive power and effluent treatment plants, essential equipment required in operations areas such as clean rooms, air curtains, temperature and air quality control systems, compressed air, water & power supply, and control systems. Associated utilities would also

include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, software, and ERP solutions. All non-creditable taxes and duties would be included in such expenditure.

2.9.2. Expenditure incurred on Research and Development (R&D):

Capital expenditure on R&D and product development related to Target Segments. The term “related” here refers to all stages in the entire value chain of the goods proposed to be manufactured including software integral to the functioning of the same. Such expenditure shall include expenditure on in-house and captive R&D, directly attributable to goods covered under Target Segments, including all stages in the entire value chain of the goods proposed to be manufactured including software integral to functioning of the same. Such expenditure shall include test and measuring instruments, prototypes used for testing, purchase of design tools, software cost (directly used for R&D) and license fee, expenditure on technology, IPR, Patents and Copyrights for R&D. All non-creditable taxes and duties would be included in such expenditure.

2.9.3. Expenditure related to Transfer of Technology (ToT)

Agreements: This shall include cost of technology and initial technology purchase related to goods covered under Target Segments. All non-creditable taxes and duties would be included in such expenditure.

2.9.4. Expenditure incurred on Land and Building:

The expenditure incurred on land and building (including factory building / construction) required for the project / unit is not covered under

the Scheme and, therefore, will not be considered for determining eligibility under the Scheme.

**2.10. Eligible Product:** Good manufactured in India and covered under Target Segments with threshold on invoice value as applicable and annexed in the Scheme and in Annexures 1 and 2 of these Guidelines.

**2.11. Invoice Value:** Unit Price charged on an invoice raised by an applicant on sale of manufactured goods, net of credit notes, discounts or any other adjustments and applicable taxes.

**2.12. Net Sales Turnover:** Net Sales Turnover shall mean the Gross Sale Turnover net of credit notes (raised for any purpose), discounts (including but not limited to cash, volume, turnover, target or for any other purpose) and taxes applicable.

**2.13. Financial Year:** Financial Year begins on the 1st April of a year and ends on 31st March of the following year.

**2.14. Base Year:** In accordance with Para 7 of the Scheme, Financial Year 2019-20 shall be treated as the Base Year.

**2.15. Manufacturing:** In accordance with Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017; manufacturing shall mean processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “manufacturer” shall be construed accordingly.

**2.16. Incremental Investment:** Investment made in India after the end of the Base Year as defined.

**2.17. Incremental Sales of Manufactured Goods:** Sales of Manufactured Goods over a given period minus the Sales of Manufactured Goods in the Base Year over the corresponding period.

**2.18. Employment:** Jobs which are directly involved in the production process or with related activities beginning from when materials enter a production facility and up until the resultant manufacturing good

leaves the production facility. Such employment shall include on-roll, contractual and apprentice workforce in the country only.

**2.19. Non-Originating Material and Services:** Material and Services whose country of origin is other than the country in which that material / service is used in manufacturing and any material / service whose origin cannot be determined.

**2.20. Domestic Value Addition:** Domestic Value addition shall be computed as below (A divided by B):

A. Net Sales Turnover minus value of non-originating Material and Services used in manufacturing

B. Net Sales Turnover

**2.21. Successor-in-Interest:** Successor-in-Interest shall mean the new or re-organized entity formed after the merger, demerger, acquisition, transfer of business or significant change in ownership of an applicant.

**2.22. Related Party(ies):** The term related party shall be as defined in Accounting Standard-18: Related Party Disclosures or Indian Accounting Standard (Ind-AS)-24 Related Party Disclosure, as may be applicable to the applicant, as notified by Ministry of Corporate Affairs or any other appropriate authority from time to time.

**2.23. Force Majeure:** Extraordinary events or circumstances beyond human control such as an event described as an act of God (like a natural calamity) or events such as a war, strike, public health emergency, riots, crimes (but not including negligence or wrong-doing, predictable / seasonal rain and any other events specifically excluded).

**2.24. Competent Authority:** Competent Authority under the Scheme shall be defined as per delegation of powers for appraisal and approval of Public Funded Schemes and Projects vide OM No. 24(35)/PF-II/2012 dated 05.08.2016 issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance or any subsequent modifications thereof.

**2.25. Domestic Company(ies):** Domestic Company(ies) shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Circular of 2017. A company is considered as 'Owned' by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and / or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens.

**2.26. Group Company(ies):** Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:

- Exercise twenty-six percent or more of voting rights in other enterprise; or
- Appoint more than fifty percent of members of board of directors in the other enterprise.

As defined in the FDI Policy Circular of 2017.

**2.27. Mobile Phone:** Mobile Phone for the purpose of target segment and eligibility of incentive under this Scheme shall mean a mobile phone complete in all respect for sale to a consumer.

### **3. Qualification and Eligibility**

**3.1.** Support under the Scheme shall be provided only to companies engaged in manufacturing of goods in India as covered under Target Segments.

**3.2.** Eligibility shall be subject to qualification criteria for applicants under different Target Segments in the Scheme are as defined

#### **3.2.1. Mobile Phones:**

3.2.1.1. For category *Mobile Phones (Invoice Value INR 15,000 and above)*; Consolidated Global Manufacturing Revenue of the applicant (including its

Group Companies), in the target segment, **should be more than INR 10,000 Crore in the base year.**

3.2.1.2. For category *Mobile Phones (Domestic Companies)*; Consolidated Global Manufacturing Revenue of the applicant (including its Group Companies), in the target segment, **should be more than INR 100 Crore in the base year.** Applicants under this category can only be Domestic Companies as defined in Para 2.25.

3.2.2. **Specified Electronic Components:** Consolidated Global Manufacturing Revenue of the applicant (including its Group Companies), in the target segment, **should be more than INR 50 Crore in the base year.**

3.3. Eligibility shall be subject to thresholds of Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under Target Segments) over the base year as defined.

3.3.1. An applicant must meet threshold criteria to be eligible for disbursement of incentive for the year under consideration. Eligibility threshold criteria are annexed in the Scheme and in **Annexure 2** of these Guidelines.

3.3.2. In case an applicant does not meet threshold criteria for any given year, the applicant shall not be eligible for incentive in that particular year. However, the applicant will not be restricted from claiming incentive in subsequent years during the tenure of the Scheme, provided eligibility criteria are met for such subsequent years.

3.4. For the purpose of determining eligibility of an applicant under the Scheme, in order to meet the threshold criteria of Incremental Investment for any year, the **cumulative value of investment done till**

**such year** (including the year under consideration) over the Base Year shall be considered.

- 3.5.** For the purpose of determining eligibility of an applicant under the Scheme, in order to meet the threshold criteria of Incremental Sales of Manufactured Goods covered under Target Segments for any year, the Total Sales of Manufactured Goods covered under Target Segments **for such year over the Base Year, irrespective of Invoice Value** (whether below or above INR 15,000 in case of Mobile Phones) shall be considered.
- 3.6.** Eligibility under PLI Scheme shall not affect eligibility under any other scheme and vice-versa.

#### **4. Investment for Determining Eligibility**

##### **4.1. General Terms and Conditions**

- 4.1.1. Investment as defined in Para 2.9 of these Guidelines shall be considered for determining eligibility under the Scheme provided such **Investment is made on or after 01.04.2020.**
- 4.1.2. Expenditure on consumables and raw material used for manufacturing shall not be considered as Investment.
- 4.1.3. The date of invoice would be considered as the date of investment under the Scheme.
- 4.1.4. The heads of Investment, based on which eligibility is being determined, must be capitalized in the books of accounts of the applicants.

##### **4.2. Plant, Machinery and Equipment**

- 4.2.1. Expenditure incurred on Plant, Machinery & Equipment as defined in Para 2.9.1 of these Guidelines shall be considered as Investment for determining eligibility under the Scheme.

- 4.2.2. Plant, machinery, and equipment must be purchased / leased in the name of the applicant. In cases where these are being leased, the lease should be in the nature of a financial lease within the meaning of Accounting Standard 19 – Leases or Indian Accounting Standard (Ind-AS) – 116 Leases, as may be applicable to the applicant, as notified by Ministry of Corporate Affairs or any other appropriate authority from time to time.
- 4.2.3. The used / refurbished plant, machinery and equipment allowed under the Scheme shall have a minimum residual life of at least 5 years as per Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, amended vide Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification dated 11.06.2018. Further, a valuation certificate by a Chartered Engineer assessing the value and residual life shall also be required. In case of import, such valuation should be in accordance with Customs Valuation Rules and Circulars. The value of these plant, machinery and equipment shall be considered as lower of depreciated value (as per scale of depreciation fixed by Customs, whether these plant, machinery and equipment are imported or not) and the value assessed by Chartered Engineer (of India) or equivalent overseas chartered engineer.
- 4.2.4. In such case that tools, dies, moulds, jigs, fixtures and parts, accessories, components and spares are located outside the premises of an applicant, appropriate undertaking(s) from the person having custody of these equipment / components along with valid legal agreement(s) for the said transaction(s) shall be obtained. These equipment / components should not be located outside the country.

- 4.2.5. Plant, machinery, and equipment shall be procured / leased through legally valid documents after payment of applicable taxes and duties.
- 4.2.6. The plant, machinery and equipment approved under the Scheme should be used in regular course for manufacturing of the goods under the Target Segments that are approved in the approval letter issued by PMA. This does not preclude the usage of such machinery for manufacturing of other electronic goods. The applicant must submit a declaration about usage of machinery for each year during the period that such applicant is claiming incentive under the scheme.
- 4.2.7. The PMA will rely on certificates from Chartered Engineer or any valuer registered with Insolvency & Bankruptcy Board of India, and valuation considered under Customs Rules, wherever applicable, for the purpose of determining reasonableness of cost.

#### **4.3. Research and Development (R&D)**

- 4.3.1. Expenditure incurred on Research and Development as defined in Para 2.9.2 of these Guidelines shall be considered as Investment for determining eligibility under the Scheme.
- 4.3.2. The applicant shall provide a statutory auditor certificate and purchase agreements in respect of the cost of technology, IPRs, patents and copyrights.
- 4.3.3. The software associated with R&D shall be procured / licensed through legally valid documents after payment of applicable taxes and duties.

#### **4.4. Transfer of Technology Agreements**

- 4.4.1. Expenditure incurred on Transfer of Technology Agreements as defined in Para 2.9.3 of these Guidelines shall be considered as Investment for determining eligibility under the Scheme.

4.4.2. The applicant shall provide a statutory auditor certificate in respect of expenditure related to Transfer of Technology Agreements.

#### **4.5. Associated Utilities**

4.5.1. Expenditure incurred on associated utilities as defined in Para 2.9.1 of these Guidelines shall be considered as Investment for determining eligibility under the Scheme.

4.5.2. The associated utilities will be capped at rates specified in the CPWD schedule of rates for items whose rates are available under CPWD schedule of rates.

4.5.3. The applicant shall provide a statutory auditor certificate in respect of expenditure related to associated utilities.

#### **4.6. Related Party Transactions**

4.6.1. All transactions with Related Parties will be subject to provisions of relevant statutes and Accounting Standard-18 as amended from time to time.

### **5. Application**

**5.1.** The Scheme shall be **open for applications till 31.07.2020** initially which may be extended.

**5.2.** The Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the industry.

**5.3.** An application under the Scheme can be made to MeitY / Project Management Agency (PMA) by any company registered in India.

**5.4.** The number of applications allowed per applicant for support under the Scheme shall be restricted to one (1).

**5.5.** Each application shall be limited to one of the Target Segments. However, an applicant may make another application for a particular

Target Segment if the previous application has been rejected and closed by MeitY / PMA post examination.

- 5.6.** Incentives, at any point of time, will be limited to applications approved under the Scheme.
- 5.7.** An application shall be made in the format provided in **Annexure 3** of these Guidelines and as per the process mentioned in Para 6 of these Guidelines.
- 5.8.** On receipt of an application in the prescribed format, MeitY / PMA will conduct an examination as to whether the application prima facie meets the criteria as prescribed in **Annexure 4** of these Guidelines. The aforesaid prima facie examination shall be completed within 15 working days from the date of receipt of the original application or any subsequent submission of the revised application if the original filling was returned as incomplete earlier. No original application will be accepted after the end of the application window.
- 5.9.** In cases, where on the above-mentioned examination, an application is found to be incomplete, MeitY / PMA shall inform the applicant accordingly within 15 working days of receipt of the application. An applicant must complete an incomplete application within 10 working days of such communication from MeitY / PMA, failing which, the application will be closed under intimation to the applicant.
- 5.10.** For an application which prima facie meets the criteria as prescribed in Annexure 4 of these Guidelines, MeitY / PMA shall issue an acknowledgement of receipt of the application within 15 working days of receipt of application. This acknowledgement shall not be construed as approval under the Scheme. In cases, where on examination it is found that an original or a revised application does not prima facie meet the criteria as prescribed, MeitY / PMA shall inform the applicant

accordingly within 15 working days of receipt of application and the application shall be closed.

- 5.11.** A non-refundable application fee would be payable for each application. The application fee, as mentioned in Annexure 5 of these Guidelines, would be accepted electronically only.
- 5.12.** Applications received during the Application Window will be appraised on an ongoing basis and considered for approval.

## **6. Online Portal**

- 6.1.** All applications will be submitted through an online portal to MeitY / Project Management Agency (PMA). In case, the portal is not available, applications may be submitted in physical form, addressed to Joint Secretary (Electronics), IPHW Division, Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi –110003.
- 6.2.** Upon successful submission of an application, MeitY / PMA will issue a unique Application ID to the applicant for all future activities pertaining to the Scheme. All applicants may refer to this unique ID for any future correspondence on the subject.
- 6.3.** Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) may separately issue detailed instructions for the use of online portal for PLI.

## **7. Project Management Agency (PMA)**

- 7.1.** The Scheme will be implemented through a Nodal Agency as mentioned in Para 11.1 of the Scheme. Such nodal agency shall act as a Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing

secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time.

**7.2.** The PMA would be responsible for inter-alia:

7.2.1. Receipt of application, examination and appraisal of applications and issuing acknowledgements.

7.2.2. Making appropriate recommendations to the Empowered Committee (EC) for approval of applications under the Scheme.

7.2.3. Determination of Baseline for Sales of Manufactured Goods and Investment for approved applicants and making appropriate recommendations to the EC.

7.2.4. Verification of thresholds for determining eligibility for disbursement of incentive.

7.2.5. Examination of claims for disbursement of incentive and making appropriate recommendations to the EC.

7.2.6. Verification of the reconciliation of disbursement claims with prescribed documents.

7.2.7. Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme through Quarterly Review Reports and other information / documents

**7.3.** The PMA may request for additional information, details and documents from the applicant as deemed necessary.

**7.4.** The PMA shall have the right to carry physical inspection of an applicant's manufacturing units and offices through site visit.

## **8. Empowered Committee (EC)**

**8.1.** An Empowered Committee (EC) shall be constituted in accordance with Para 12 of the Scheme. The EC shall include CEO NITI Aayog,

Secretary Economic Affairs, Secretary Expenditure, Secretary MeitY, Secretary Revenue, Secretary DPIIT and DGFT.

- 8.2.** The EC shall meet as often as necessary to ensure timely consideration of applications and disbursement claims and conduct periodic review of the Scheme.
- 8.3.** The EC will consider applications, as recommended by the PMA for approval under the Scheme and make appropriate recommendations to the Competent Authority. The EC may seek such additional information, as necessary for making its recommendation.
- 8.4.** The EC while considering applications for approval and making recommendations to the Competent Authority, shall ensure that the total amount of incentives payable across target segments do not exceed the Financial Outlay as indicated in Para 8.1 of the Scheme irrespective of the number of applicants under different Target Segments.
- 8.5.** The EC will consider baselines, as determined by the PMA for approval. The EC may seek such additional information, as necessary for giving approval of baselines.
- 8.6.** The EC will consider claims for disbursement, as examined, and recommended by the PMA, for disbursement of incentive.
- 8.7.** The EC will conduct a periodic review of eligible companies with respect to their investments, employment generation, production and value addition under the Scheme.
- 8.8.** The EC may revise incentive rates, ceilings, Target Segments, and eligibility criteria as deemed appropriate during the tenure of the Scheme.
- 8.9.** In case of a Force Majeure event, the EC may amend, modify, or withdraw any clauses under the scheme.

**8.10.** The EC may hold stakeholder consultation as and when deemed necessary during the tenure of the scheme.

**8.11.** The EC will also be authorized to carry out any amendments in Scheme Guidelines.

## **9. Approval under PLI**

**9.1.** The Project Management Agency (PMA) appointed by MeitY, will appraise the applications, as received, after issuing of acknowledgements. The PMA shall accordingly make appropriate recommendations to the Empowered Committee (EC) for approvals under the Scheme.

**9.2.** The Empowered Committee will consider applications, as recommended by the PMA for approval under the Scheme and make appropriate recommendations to the Competent Authority for approval of applications.

**9.3.** After the conclusion of initial round of applications, approvals will be granted to **not more than 5 eligible applicants in Target Segment *Mobile Phones (Category – Invoice Value INR 15,000 and above); not more than 5 eligible applicants in Target Segment *Mobile Phones (Category – Domestic Companies); and not more than 10 eligible applicants in Target Segment *Specified Electronic Components.*****

**9.4.** In case of receipt of eligible applications in excess of the limits specified above for any of the Target Segments, the eligible applications for the given Target Segment will be ranked from highest to lowest on the basis of consolidated global manufacturing revenue of the applicants (including its group companies), in the target segment, in the base year. **5 eligible applicants having the highest**

**consolidated global manufacturing revenue in Target Segment *Mobile (Category – Invoice Value INR 15,000 and above)*; 5 eligible applicants having the highest consolidated global manufacturing revenue in Target Segment *Mobile (Category – Domestic Companies)*; and 10 eligible applicants having the highest consolidated global manufacturing revenue in Target Segment *Specified Electronic Components*; shall be selected and granted approval under the Scheme.**

**9.5.** After receiving approval from the Competent Authority, the PMA shall issue a letter to the applicant within 5 working days, communicating approval under the Scheme. The approval letter shall clearly state the following:

9.5.1. Name of Applicant

9.5.2. Target Segment

9.5.3. Eligible Product

9.5.4. Yearly Thresholds of Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment, applicable for determining eligibility

9.5.5. Yearly Ceiling on Incremental Sales of Manufactured Eligible Product on which incentive shall be applicable.

9.5.6. Plan for Domestic Value Addition during the tenure of the Scheme

9.5.7. Plan for Employment Generation in India during the tenure of the Scheme

**9.6.** The aforesaid approval letter shall not be construed as a guarantee for disbursement of incentive as the same will be dependent upon verification of eligibility after submission of disbursement claim and other criteria defined in these Guidelines.

## **10. Baseline for Investment and Sales of Manufactured Goods for Eligibility and Incentive**

**10.1.** Eligibility under the Scheme is subject to thresholds of Incremental Investment, and Incremental Sales of Manufactured Goods covered under Target Segments as defined. Accordingly, a baseline for Investment and Sales of Manufactured Goods will have to be established to determine eligibility and compute incentive amount due.

**10.2.** The period for determination of baseline shall be as follows:

10.2.1. Baseline for Investment: As on 31.03.2020

10.2.2. Baseline for Sales of Manufactured Goods

a) First year i.e. FY 2020-21: Period from 01.08.2019 to 31.03.2020

b) Second year onwards: Period from 01.04.2019 to 31.03.2020

**10.3.** Applicants shall be required to submit information / documents, as deemed necessary for establishing the baseline, including but not limited to statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries / Departments / Agencies, or any other document sought by the PMA.

**10.4.** The PMA shall determine the baseline based on information / documents submitted by the applicant. This process will be completed within 30 working days from the submission of all necessary documents and receipt of clarifications sought by the PMA. The PMA shall accordingly make appropriate recommendations to the Empowered Committee (EC) for approval of the baseline.

**10.5.** The EC will consider baselines of investment and Sale of Manufactured Goods, as determined by the PMA for granting approval of such baselines under the scheme.

**10.6.** After receiving approval from the Empowered Committee, the PMA shall issue a letter to the applicant within 5 working days communicating the same. The letter shall clearly state with reference to earlier communication, the following:

10.6.1. Name of Applicant

10.6.2. Target Segment

10.6.3. Eligible Product

10.6.4. Application Acknowledgement Date

10.6.5. Application Approval Date

10.6.6. Thresholds of Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment, applicable for determining eligibility

10.6.7. Baseline for Investment (as on 31.03.2020)

10.6.8. Baseline for Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment and for Sales of Manufactured Eligible Product for first year (Period from 01.08.2019 to 31.03.2020)

10.6.9. Baseline for Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment and for Sales of Manufactured Eligible Product for second and subsequent years (Period from 01.04.2019 to 31.03.2020)

10.6.10. Any other information / condition stipulated by the EC

**10.7.** No disbursement claims will be considered until the process of determining the baseline has been completed for an approved application.

## **11. Calculation of Incentive**

**11.1.** The incentive applicable for an approved applicant shall be computed as follows:

## **Net Incremental Sales of Eligible Product x Rate of Incentive**

Where

- Eligible Product is as stated in the approval letter
- Net Incremental Sales shall be Net Sales Turnover of Eligible Product for the period to which claim for disbursement of incentive pertains minus the Net Sales Turnover of said Eligible Product as per baseline determined
- In case of return of Sales of Manufactured Goods under target segments, the Gross Sale Turnover shall be reduced by the amount corresponding to such return of sales. If the corresponding sales have been considered for claim processing for the earlier period, the sales return shall be adjusted with Gross Sale Turnover for the period in which the actual sales return takes place.
- The incentive amount payable shall be subject to annual and cumulative ceilings on Net Incremental Sales Turnover on which incentive shall be applicable.
- Annual Ceiling on incentive payable to each applicant will be determined based on Financial Outlay as indicated in Para 8.1 of the Scheme and number of eligible applicants in each of the target segments. The annual financial outlay will be appropriated proportionately depending on number of applicants under each target segment. At the end of the year, any unappropriated incentive amount resulting from underperformance with respect to the prescribed annual ceiling on Net Incremental Sales, by any applicant(s) in any target segment, will be allocated to the remaining eligible applicants under such target segment who have achieved Net Incremental Sales in excess of the annual ceiling . Such incentive amount will be distributed only to the extent of excess performance by an applicant beyond the annual ceiling of net incremental sales of eligible product. If the incentive amount payable on cumulative excess performance by the applicants in a target segment is greater than the unappropriated incentive amount, then the sum of incentives

payable beyond the ceiling amount for each applicant will be restricted to the unappropriated incentive amount for such target segment and such amount will be distributed among the overperforming applicants in proportion to their respective excess performance beyond the annual ceiling of Net Incremental Sales.

- **Illustratively**, if there are five (5) eligible applicants under *Mobile Phones(Invoice Value of INR 15,000 and above)* target segment, the year-wise incentive ceiling per applicant will be 1/5<sup>th</sup> of the annual financial outlay for the said target segment. In case of underperformance by say 2 applicants, the unappropriated amount relating to these applicants will be allocated to the 3 remaining applicants in proportion to their performance in excess of the annual ceiling of Net Incremental Sales. **Excess incentive payable to each of these 3 applicants will be capped to the lower of the following:**

(i) Incentive payable on excess performance beyond annual ceiling of net incremental sales at the eligible rate of incentive for such year.

OR

(ii) Share of unappropriated incentive amount, divided in proportion to the excess performance by the applicants over the annual ceiling of Net Incremental Sales for such applicants.

## **12. Disbursement of Incentives**

**12.1.** For claiming incentive under the Scheme, applicants will be required to submit claims for disbursement of incentive to the PMA. Applicants must ensure that the claims are complete in all respects and are accompanied by all the documents required as per format prescribed in Annexure 6 of these Guidelines.

**12.2.** An applicant may submit a claim for disbursement of incentive as early as the end of the quarter in which the eligibility criteria for the year in consideration have been met. Claims for disbursement of incentive may

be submitted only on a quarterly or half-yearly or annual basis. Claims for any period shall be made only once, unless withdrawn, and no subsequent part claims shall be allowed for the said period.

- 12.3.** Claims for disbursement of incentive shall be filed by the applicants within 9 months from the end of the financial year to which the claim pertains.
- 12.4.** The PMA will examine the disbursement claims as submitted by an applicant. The PMA shall verify eligibility and assess incentive payable to an applicant based on the method laid down in these Guidelines and the approval letter issued to the applicant.
- 12.5.** The PMA will have the right to verify any document(s) in relation to the claim for incentives including but not limited to statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries / Departments / Agencies. The PMA shall also have the right to examine the end realization and settlement / payments corresponding to sales and investment respectively by way of auditor's certificate, bank statements etc. to the extent deemed necessary.
- 12.6.** In case of any doubt with respect to determining eligibility and incentive amount due, or any other matter in discharge of its duties and responsibilities, the PMA may refer to MeitY for clarification. The decision of MeitY will be final in this regard.
- 12.7.** The PMA shall process claims for disbursement of incentive and make appropriate recommendations to the EC.
- 12.8.** The EC will consider claims for disbursement, as examined, and recommended by the PMA, for disbursement of incentive.
- 12.9.** The PMA shall disburse funds after completion of all pre-disbursal formalities by the applicant and approval from Competent Authority.
- 12.10.** The disbursement of incentives may be in the form of Direct Bank Transfer (to be used as may be allowed by the Ministry of Finance)

through PFMS, or through any other mechanism of adjustment in the name of the applicant only.

- 12.11.** Applicants shall be required to reconcile Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured Goods, based on which claims for disbursement of incentive have already been filed, with documents as prescribed by the PMA, by 31st of December of the financial year subsequent to which the claim pertains.
- 12.12.** The PMA shall verify the aforesaid reconciliation. In case of excess claims disbursed, the applicant shall reimburse MeitY for any incentive amount refundable along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually (for the period between excess payment and date of refund by the applicant).
- 12.13.** If the PMA or MeitY is satisfied that eligibility under the Scheme and / or disbursement of incentives have been obtained by misrepresentation as to an essential fact or furnishing of false information, MeitY may ask the applicant to refund the incentives along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard, subject to conditions stipulated in Para 14.4.
- 12.14.** MeitY shall make budgetary provisions for disbursal of incentives by the PMA under the Scheme. The PMA will submit budgetary requirements to MeitY as a consolidated amount on a quarterly basis.
- 12.15.** The PMA shall furnish information to MeitY with details of disbursement claims received for incentives, amount disbursed, reasons for rejection / delay in disbursement of the incentives on a quarterly basis.

## **13. Review**

- 13.1.** Periodic reviews will be undertaken by the Empowered Committee (EC) with respect to progress and performance of the Scheme and changes, if any, to incentive rates, ceilings, Target Segments, and eligibility criteria.
- 13.2.** All approved applicants shall be required to furnish self-certified Quarterly Review Reports (QRRs) within 30 days from the end of each quarter in the format provided in Annexure 7 of these Guidelines.

## **14. Residual**

- 14.1.** Incentive shall not be claimed for a given manufactured item under one target segment by more than one applicant.
- 14.2.** An applicant shall intimate the PMA of any change in the shareholding pattern during the tenure of the Scheme, after updation with the Registrar of Companies (RoC).
- 14.3.** Any change in the shareholding pattern of an applicant leading to a successor-in-interest or having the effect of change in nature of company as per Annexure 2 of the Guidelines during the tenure of the Scheme, shall be intimated by PMA for approval of the EC to consider for disbursement of incentives.
- 14.4.** In case of a successor-in-interest or having the effect of change in nature of company as per Annexure 2 of the Guidelines, all Incremental Investment undertaken by the applicant to whom approval was accorded under the Scheme, would be considered for determining eligibility, subject to approval and compliance with any other condition stipulated by the EC, as may be deemed appropriate. The baseline

applicable for the successor-in-interest will be the same as determined for the applicant to whom approval was accorded under the Scheme.

- 14.5.** To obviate any malpractices in the financial matters where disbursements are made to industry by the Government, it has been decided to provide a deterrent against corrupt practices for promotion of transparency and equity. Therefore, keeping in view the sensitivities involved in the process and taking cue from the instructions of the Central Vigilance Commission regarding adoption of an Integrity Pact in the matter of procurement, it has been decided to obtain undertaking(s) from applicants under the Scheme.
- 14.6.** Two formats of undertakings are enclosed as Format-A and Format-B in Annexure 8. These undertakings are to be furnished by applicants, duly signed by CEO / MD / Director, and depicting the designation along with authorization to do so.
- 14.7.** The first undertaking (Format-A) shall be provided by all applicants whose applications or claims are under consideration for approval or disbursement of incentives. The applications or claims of those applicants who do not submit the undertaking shall not be processed and considered. The second undertaking (Format-B) for confirming the compliance of integrity will be provided by applicants after the submission of claims for disbursement of incentive and in any case before release of funds. The release of incentives shall be withheld until the above-mentioned undertaking is provided.



**(Saurabh Gaur)**

**Joint Secretary to the Government of India**

**Tel No. 011-24363071**

**Email: saurabh.gaur@meity.gov.in**

**New Delhi, Dated: June 1, 2020**

**Copy to:**

1. **All Concerned Ministries / Departments of Government of India**
2. **All States / Union Territories**
3. **Cabinet Secretariat**
4. **PMO**
5. **NITI Aayog**
6. **Comptroller and Auditor General of India**
7. **AS&FA, Ministry of Electronics and Information Technology**
8. **Industry Associations**
9. **Implementation agencies of projects under EMC scheme.**
10. **Internal circulation**

*Saurabh Gaur*  
(Saurabh Gaur)

**Joint Secretary to the Government of India**

**Tel No. 011-24363071**

**Email: saurabh.gaur@meity.gov.in**

## Target Segments Eligible under PLI

S. No.	Description of Goods
1.	<b>Mobile Phones</b>
2.	<b>Specified Electronic Components</b>
2.1	SMT components
2.2	Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, thyristors, etc.
2.3	Passive components including resistors, capacitors, etc. for electronic applications
2.4	Printed Circuit Boards (PCB), PCB laminates, prepregs, photopolymer films, PCB printing inks
2.5	Sensors, transducers, actuators, crystals for electronic applications
2.6	System in Package (SIP)
2.7	Micro / Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
2.8	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

## Eligibility Threshold Criteria

Segment	Incentive Rate (on Incremental Sales of Manufactured Goods)	Incremental Investment	Incremental Sales of Manufactured Goods
Mobile Phones (Invoice value of INR 15,000 and above) *	Year 1: 6% Year 2: 6% Year 3: 5% Year 4: 5% Year 5: 4%	INR 1,000 Crore Over 4 Years Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 250 Year 2: 500 Year 3: 750 Year 4: 1,000	Year 1: INR 4,000 Crore Year 2: INR 8,000 Crore Year 3: INR 15,000 Crore Year 4: INR 20,000 Crore Year 5: INR 25,000 Crore
Mobile Phones (Domestic Companies)		INR 200 Crore over 4 Years Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 50 Year 2: 100 Year 3: 150 Year 4: 200	Year 1: INR 500 Crore Year 2: INR 1,000 Crore Year 3: INR 2,000 Crore Year 4: INR 3,500 Crore Year 5: INR 5,000 Crore
Specified Electronic Components (detailed in <i>Annexure 1</i> )		INR 100 Crore over 4 Years Cumulative Minimum (Crore): Year 1: 25 Year 2: 50 Year 3: 75 Year 4: 100	Year 1: INR 100 Crore Year 2: INR 200 Crore Year 3: INR 300 Crore Year 4: INR 450 Crore Year 5: INR 600 Crore

**\*For eligibility, all Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under Target Segments) irrespective of Invoice Value shall be considered.**

**Application Form: Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing**

**1. Introduction**

- 1.1.** The application shall be duly signed by authorized signatory of legal entity.
- 1.2.** Applicants are advised to follow the format provided in this template for submitting their applications. Applicants are requested to provide information and enclose all supporting documents as detailed.
- 1.3.** All applications shall be submitted through an online portal to MeitY / Project Management Agency (PMA) notified under the Scheme. In case, the portal is not available, applications may be submitted in physical form to IPHW Division, Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003. A non-refundable application fee of Rs. 1,00,000 (One lakh only) would be payable for each application. The application fee, as mentioned in Annexure 5 of these Guidelines, would be accepted electronically only.
- 1.4.** Applicants may go through the Guidelines carefully before filling up the details in the application.
- 1.5.** Application has been divided into the following sections and sub-sections:
  - I.** Applicant Details
  - II.** Proposal
  - III.** Application Fee Details

- 1.6.** If any document which is required to be submitted along with the application is available on a government website, the website link where this document can be viewed may be provided. The responsibility of the correctness / veracity of contents rest with the applicant(s).

## **2. Section I – Applicant Details**

### **2.1. Name of Applicant**

- 2.2. Company Structure** (entity) under which the project is to be undertaken (legal status, shareholding pattern and details of relevant agreements which might have been signed with business partner(s), if any). The agreement and roles and responsibilities between the partners must be clearly mentioned

*Documents to be furnished:* Certified copy of the memorandum and articles of association or equivalent registration document

- 2.3. Company Details:** Address, phone, email, PAN, nature of current business, turnover etc. Include brief profile of Chairman, Chief Executive Officer and other CXO level officers.

*Documents to be furnished:*

- a) Self-certified copies of PAN, GST Certificate for applicant,
- b) Self-certified copies of brief profile of Chairman, CEO and CXOs
- c) Self-certified certified copies of Annual Reports including Annual Financial Reports along with schedules for 3 years. Most recent reports to be provided.

- 2.4. Credit History:** Please provide details of presence in RBI's Defaulter and Wilful Defaulter Lists, SEBI Debarred List and CIBIL Score.

*Documents to be furnished:*

- a) Certificate from Company Secretary / Board of Directors

- 2.5. Key Personnel Details:** Contact details of three senior employees of applicant. Details would include Name, Designation, Address, phone, email

- 2.6. Qualification Criteria (self-certified):** Consolidated Global Manufacturing Revenue of the applicant (including Group Companies), in the Target Segment

*Documents to be furnished:* Self-Certified Annual Returns of parent company.

- 2.7. Financial Details (self-certified):**

- a) Revenue (INR Cr) – Total and Target Segment – Manufacturing split by Exports, Domestic Sale (last 3 years)
- (i) Such information must be furnished separately for the period from 01.08.2019 to 31.03.2020
- (ii) Further, in case of the *Mobile Phones* Target Segment, information on revenue for Eligible Products must be furnished separately for FY 2019-20 and for the period from 01.08.2019 to 31.03.2020
- b) Profit before Tax (PBT) and Profit after Tax (PAT) (INR Cr) – Target Segments (last 3 years)
- c) Details of Funds - Received from government / owners or other financing agencies, multi-lateral agencies / other institutions to

fund expansion (last 3 years). Equity and debt to be shown separately.

### **3. Section II – Proposal**

#### **3.1. Eligible Product and Target Segment**

#### **3.2. Projections (self-certified):**

- a) Forecasted Revenue –Total and Target Segment –Manufacturing split by Exports, Domestic Sale (next 5 years)
- b) Proposed Plan for Domestic Value Addition (next 5 years)
- c) Proposed Plan for Employment Generation in India (next 5 years)

#### **3.3. Size of Investment (INR Cr)**

Size of the investment must include the capital expenditure expected to be incurred in next 4 years. The following details should be furnished:

- a) Details of Investment – Existing and Proposed
- b) Sources of Funding (internal accruals, equity, government assistance, term debt and working capital loans etc.)

#### **3.4. Regulatory Treatment**

- a) Provide information on Licenses, permits and third-party approvals necessary to execute the project.
- b) Proposed process and timelines for obtaining clearances.

### **4. Section III –Application Fee Details**

#### **4.1. Proof of the Application Fee Submission**

**Criteria: Documents / Information to be checked for preliminary assessment of application**

1. Submission of prescribed Application Fee.
2. Products proposed are covered under Target Segments.
3. Applicant is eligible for proposed Target Segment.
4. Proposed investment is greater than or equal to the threshold applicable under proposed Target Segment (as per Annexure 2 of the Guidelines)
5. Proposed Incremental Sales of Manufactured Goods covered under proposed Target Segment are greater than or equal to the threshold applicable under proposed Target Segment (as per Annexure 2 of the Guidelines)

**Note:** It may be noted that acknowledgement based on above does not qualify an applicant for claiming incentives under the Scheme. The applicant would be eligible for incentives after approval, baseline determination and achieving eligibility as per procedure defined in the Scheme Guidelines

**Application Fee for Application under PLI**

An amount of INR 1,00,000 is hereby notified under Para 5.11 of the said Guidelines as application fees, which shall be paid electronically through NEFT/RTGS to the MeitY / PMA.

**Disbursement Claim Form: Production Linked Incentive Scheme (PLI)  
for Large Scale Electronics Manufacturing**

- 1.** Applicant Name
- 2.** Target Segment
- 3.** Eligible Product
- 4.** Application Acknowledgement Date
- 5.** Ref. No. and Date of Approval Letter
- 6.** Thresholds of Incremental Investment and Incremental Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment applicable for determining eligibility
- 7.** Baseline for Investment (as on 31.03.2020)
- 8.** Baseline for Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment and for Sales of Manufactured Eligible Product for first year (Period from 01.08.2019 to 31.03.2020)
- 9.** Baseline for Sales of Manufactured Goods covered under Target Segment and for Sales of Manufactured Eligible Product for second and subsequent years (Period from 01.04.2019 to 31.03.2020)
- 10.** Period for which Incentives are being sought
- 11.** Applicable Ceilings as per Approval Letter

12. Certificate from Statutory Auditor covering details in the format below:

S. No.	Particulars	Unit	Base Year	Period of Claim
1	Investment as on Date of Filing Claim (Cumulative)	INR Crore		
2	Employment as on Date of Filing Claim (Cumulative)	Numbers		
3A	<b>Revenue from Operations – Domestic Sales</b> [net of credit notes, discounts, and taxes applicable]	INR		
	a) Manufacturing Activity			
	i. Eligible Product			
	ii. Other Goods in Target Segment			
	iii. Other Goods			
	b) Trading Activity			
	i. Target Segment			
	ii. Other Goods			
	c) Services Activity			
	3B		<b>Revenue from Operations – Exports</b> [net of credit notes, discounts, and taxes applicable]	INR
a) Manufacturing Activity				
i. Eligible Product				
ii. Other Goods in Target Segment				
iii. Other Goods				
b) Trading Activity				
i. Target Segment				
ii. Other Goods				
c) Services Activity				

3C	<b>Total Revenue from Operations (Domestic Sales &amp; Exports)</b>			
4	<b>Sales Quantity [net of credit notes, discounts, and taxes applicable]</b> a) Manufacturing Activity i. Eligible Product ii. Other Goods in Target Segment iii. Other Goods b) Trading Activity	<i>Numbers</i>		
5	<b>Details of Import</b> CIF value of Imported goods at the time of Importation a) Raw Material / Parts / Components used for manufacturing i. Eligible Product ii. Other Goods in Target Segment iii. Other Goods b) Spare Parts used for manufacturing i. Eligible Product ii. Other Goods in Target Segment iii. Other Goods c) Finished Goods used for manufacturing i. Eligible Product ii. Other Goods in Target Segment iii. Other Goods	<i>INR</i>		

d) Capital Goods used for manufacturing			
i. Target Segment			
iii. Other Goods			
e) Import of Services pertaining to Target Segment			

**13. Certificates / undertakings stating / covering the following:**

13.1. No deviation in Eligible Product and Target Segment

**14. Certificate(s) from Company Secretary stating:**

14.1. All clearances required by law like statutory clearances, environmental clearances etc. have been obtained

**15. Certificate(s) from Statutory Auditor stating / covering:**

15.1. Threshold of Incremental Investment applicable has been achieved for the year in consideration

15.2. Details of Incremental Investment

15.3. Capitalization of Investment in the books of accounts of the applicant is in line with the relevant accounting standards issued by ICAI

15.4. Investment has been made in accordance with Scheme Guidelines and approval accorded by MeitY

15.5. Threshold of Incremental Sales of Manufactured Goods applicable has been achieved for the year in consideration

**16. Documents / certificates from Chartered Engineer:**

16.1. Certificate stating that the plant, machinery & equipment have been installed, the price is reasonable, as per the market value and the same are being used exclusively for manufacturing of approved Target Segment.

**17. List of documents to be submitted post approval of claim**

17.1. An undertaking from the applicant as per format given in Appendix

17.2. An agreement / indemnity bond on prescribed formats from the applicant that if at a later stage its claim is found to be false or excessive it would be liable to return the amount disbursed with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually.

17.3. Board resolution to the effect that the applicant agrees by the terms and conditions as laid down in the PLI Scheme and Guidelines while securing the incentive amount

**FORMAT OF UNDERTAKING**

**(Undertaking from the Applicant on letterhead)**

- 1.** We, .....,  
hereby, acknowledge that the incentives that would / may be provided to us under the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing, notified by Ministry of Electronics and Information Technology vide Notification X, will be provided to us based on, and after relying upon, the information provided by us to avail the said incentives.
- 2.** We hereby confirm that the information provided by us for availing the said incentives is true, correct and complete in all respects and that no material fact / information that may have an adverse impact on the information provided by us for availing the said incentives has been concealed. We acknowledge and confirm that the foregoing averment is on an on-going basis and further undertake to immediately apprise the Ministry of Electronics and Information Technology about any change in the status of the information provided by us to avail the said incentives.
- 3.** We further undertake that in the event of (i) any of the information provided by us to avail the said incentives being found false, incorrect or incomplete, or (ii) in the event of the undertakings and confirmations stated at para 2 above being found false, incorrect, incomplete or breached; we will (a) refund the entire amount of incentives availed by us along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually, for the period between excess payment and date of refund.
- 4.** We acknowledge that the remedies provided in para 3 (a) and 3 (b) above are not the exclusive remedies available with the Ministry of Electronics

and Information Technology and are without prejudice to any legal remedies available with Ministry of Electronics and Information Technology for events mentioned in Para 3 (i) and (ii) above.

### Quarterly Review Report

An applicant shall be required to provide the following information (self-certified) for quarterly review within 30 days from the end of each quarter:

<b>1. Name of Applicant</b>
<b>2. Target Segment</b>
<b>3. Eligible Segment</b>
<b>4. Application Acknowledgement Date</b>
<b>5. Application Approval Date</b>
<b>6. Manufacturing Location(s)</b>
<b>7. Customer Brand(s) (in case of Contract Manufacturers)</b>
<b>8. Investment Actualized for Manufacturing of Target Segment (amount in INR)</b>
<i>Source of Funding (Equity, Debt, Internal Accrual etc.)</i>
<b>9. Employment as on date (in numbers)</b>
<i>On-roll labour / employees</i>
<i>Contractual</i>
<i>Apprentice</i>
<b>10. Installed Production Capacity for Target Segment and Eligible Product (in numbers)</b>
<b>11. Revenue from Operations – Domestic Sales [net of credit notes, discounts, and taxes applicable]</b>
a) Manufacturing Activity
i. Eligible Product
ii. Other Goods in Target Segment
iii. Other Goods
b) Trading Activity
i. Target Segment
ii. Other Goods
c) Services Activity

<b>12. Revenue from Operations – Exports</b> <b>[net of credit notes, discounts, and taxes applicable]</b>
a) Manufacturing Activity
i. Eligible Product
ii. Other Goods in Target Segment
iii. Other Goods
b) Trading Activity
i. Target Segment
ii. Other Goods
c) Services Activity
<b>13. Total Revenue from Operations</b>
<b>14. Details of Import– CIF value of Imported Goods at the Importation</b>
a) Raw Material / Parts / Components
i. Eligible Product
ii. Other Goods in Target Segment
iii. Other Goods
b) Spare Parts
i. Eligible Product
ii. Other Goods in Target Segment
iii. Other Goods
c) Finished Goods
i. Eligible Product
ii. Other Goods in Target Segment
iii. Other Goods
d) Capital Goods
i. Target Segment
iii. Other Goods
e) Import of Services pertaining to Target Segment

**Subject: Proforma for Integrity compliance in PLI-Initial Undertaking(s)**

(To be signed by full time Director / CEO / MD of the company / firm duly depicting the designation and submitted on official stationery of the applicant along- with the authorization to do so)

**FORMAT-A**

1. Whereas, the applicant namely (*name of company with address*) has submitted an application under Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing to Ministry of Electronics and Information Technology(MeitY), Government of India seeking incentives for the application pertaining to manufacturing.....(Eligible Product) at.....(location(s)).
2. Now, therefore, the applicant including its officers / representatives commits and undertakes that he / she will take all measures necessary to prevent corruption. He / She commits to observe the following principles during his / her association / engagement with MeitY or its agencies or its consultants engaged with the process of appraisal and verification of application for the approval of application and disbursement of incentives under PLI.

**2.1** The PLI applicant will not directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the MeitY's officer(s) or consultant or agency representative (appraisal or / and verification agency appointed by MeitY to handle the application) involved in the process of dealing with application or to any third person any material or other benefit which he / she is not legally entitled to in order to obtain in

exchange any advantage of any kind whatsoever before or during or after the process of the application for grant of approval or disbursement of incentives under PLI.

- 2.2 The PLI applicant will not commit any offence under the relevant IPC / PC Act; Further, the applicant will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the MeitY.
- 2.3 The PLI applicant shall disclose the name and address of the duly authorized Agents / Representatives who will be dealing with MeitY or its agencies and the remuneration of these agents or representatives shall not include any hidden amount or component to get the work done in undue manner or causing inducement of whatsoever nature whether in cash or kind to influence the normal process or practice of work.
- 2.4 The PLI applicant will disclose any and all payments he / she has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries, other than regular employees or officials of the applicant, in connection with the grant of approval or / and disbursement of incentives.
- 2.5 The applicant will not offer any illicit gratification to obtain unfair advantage.
- 2.6 The applicant will not collude with other parties to impair transparency and fairness.
- 2.7 The applicant will not give any advantage to anyone in exchange for unprofessional behaviour.

3. The applicant declares that no pervious transgressions occurred in the last 3 years with any other Company in any country conforming to the anti-

corruption approach or with any other Public Sector Enterprises / Central or State Government or its any instrumentality in India.

4. The applicant agrees that if it is found that the applicant has made any incorrect statement on this subject, the application will be closed or rejected and MeitY reserve the right to initiate legal action of whatsoever nature. In case if MeitY has disbursed the incentives under PLI, the amount disbursed to applicant be recoverable along with interest calculated at 3 years SBI MCLR prevailing on the date of disbursement, compounded annually besides blacklisting of the applicant and initiation of legal action of whatsoever nature at the discretion of MeitY.

The contents of the above undertaking have been gone through and after understanding the same is being executed / given on.....day of ..... (month / year)

*Signature*

*(Name & designation with address)* Director / CEO / MD

**Subject: Proforma for Integrity compliance to be furnished by PLI Applicants before Release of Incentives**

(To be signed by full time Director / CEO / MD of the company / firm duly depicting the designation and submitted on official stationery of the applicant along- with the authorization to do so)

**FORMAT– B**

1. Whereas, the applicant namely *(name of company with address)* has submitted an application under Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India seeking incentives for the application pertaining to manufacturing ..... (Eligible Product) at..... (location(s)).
2. And Whereas, the applicant has submitted an undertaking for observance and commitment for Integrity vide Undertaking dated.....given under the signatures / authority of applicants ..... (name and designation) to MeitY in respect of aforesaid application.
3. And whereas, the applicant including its officers / representatives gives commitment and undertake that he / she will take all measures necessary to prevent corruption and that he / she will not directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the MeitY's officer(s) or consultant or agency representative (appraisal or / and verification agency appointed by MeitY to handle the application) involved in the process of dealing with application or to any third person any material or other benefit which he / she is not legally entitled to in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever before or during or after the process of the application for grant of approval or disbursement of incentives under PLI.

4. And whereas, the application submitted by the applicant has been given the approval by MeitY vide its communication no.....dated.....
5. And whereas, the applicant has submitted a claim for disbursement of incentive dated .... to the PMA for claiming incentives of INR.....
6. And whereas, the PMA has considered the claim for disbursement of incentive and is in the process of disbursement / release of incentives on the claim dated.....
7. Now, therefore, We hereby confirm the compliance thereof with the Integrity Undertaking submitted to MeitY duly certifying that there is no breach to the same and requests that eligible incentives under PLI be released to applicant and the amount of incentives be credited in the bank account of applicant.
8. The contents of the above Undertaking have been gone through and after duly understanding the same, is being executed / given on..... day of..... (month / year).

*Signature*

*(Name & designation with  
address) Director / CEO /  
MD*

**File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part(1)**  
**Government of India**  
**Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)**  
**IPHW Division**

**Dated:** 23<sup>rd</sup> September, 2021

**NOTIFICATION**

**Extension of Tenure of the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing – reg.**

**References:**

- i. *PLI Scheme Notification No. CG-DL-E-01042020-218990 dated 1<sup>st</sup> April, 2020 in Part – I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) [F. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*
- ii. *Guidelines for the Operation of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 1<sup>st</sup> June, 2020 [F. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*
- iii. *Addendum: Amendments in Guidelines of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 11<sup>th</sup> March, 2021 [File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part(1)]*
- iv. *Supplementary Guidelines on Second Round of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 11<sup>th</sup> March 2021 [File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part(1)]*

**1. Background**

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) notified the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing on April 01, 2020. Subsequently, Guidelines for the operation of the Scheme were notified on 01.06.2020. The first round of the Scheme was open for receiving applications till 31.07.2020.

Further, Second Round of the PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing was launched on 11.03.2021 for incentivising Electronic

Components. Under the Second Round, incentives of 5% to 3% shall be extended on incremental sales (over base year i.e. 2019-20) of goods manufactured in India and covered under the target segment, to eligible companies, for a period of four (4) years. The second round of the Scheme was open for receiving applications till 31.03.2021.

On 28.06.2021, Union Finance & Corporate Affairs Minister announced measures to provide relief to companies approved under the PLI Scheme affected by the COVID-19 pandemic. The text of the announcement is as quoted below:

*“Participating companies under the Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing have been unable to achieve incremental production targets due to disruption in production activities on account of pandemic related lockdowns, restrictions on movement of personnel, delays in installation of relocated plant and machinery and disruptions in supply chain.”*

*Given this, it has been decided to extend the tenure of the PLI Scheme launched in 2020-21 by one year i.e., till 2025-26. Participating companies will get the option of choosing a period of any five years till 2025-26 for meeting their production targets under the Scheme. Investments made in 2020-21 will continue to be counted as eligible investments.”*

2. As per Para 8.9 of the Scheme Guidelines dated 01.06.2020, *“In case of a Force Majeure event, the EC may amend, modify, or withdraw any clauses under the scheme”*. As per Para 8.11 of the Scheme Guidelines dated 01.06.2020, *“The EC will also be authorised to carry out any amendments in the Scheme Guidelines.”*

Therefore, in accordance with the announcement made by Hon'ble Finance Minister and above-mentioned provisions, the EC in its meeting held on 07<sup>th</sup> July 2021 recommended the following revisions, which have been approved by the Competent Authority:

2.1 **Extension of the Tenure of PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing:** In line with the announcements made by Hon'ble Finance Minister, the tenure of the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing is extended from the existing 5 years (FY 2020-21 to FY 2024-25) to 6 years (FY 2020-21 to FY 2025-26).

2.2 **Timelines for Incremental Production:** For First Round of PLI Scheme, 16 participating companies approved under the Scheme shall be allowed to choose a period of any 5 consecutive years between FY 2020-21 and FY 2025-26 to achieve threshold targets for incremental sales of manufactured goods (incremental production). Incentives for Year 1 will be applicable from 01.08.2020 or 01.08.2021 depending on the choice of Year 1 (FY 2020-21 or FY 2021-22).

Similarly, for second round of the PLI Scheme, 16 participating companies approved under the Scheme shall be allowed to choose a period of any 4 consecutive years between FY 2021-22 and FY 2025-26 to achieve threshold targets for incremental sales of manufactured goods (incremental production). Incentives will be applicable from 01.04.2021 or 01.04.2022 depending on the choice of Year 1 (FY 2021-22 or FY 2022-23).

2.3 **Timelines for Incremental Investment:** For the first round of the PLI Scheme, incremental investment made by participating companies in FY 2020-21 will be counted towards the incremental investment targets irrespective of the choice of Year 1 (FY 2020-21 or FY 2021-22).

Similarly, for the second round of the PLI Scheme, incremental investment made by participating companies in FY 2021-22 will be counted towards the incremental investment targets irrespective of the choice of Year 1 (FY 2021-22 or FY 2022-23).

2.4 **Annual Incentive Outlay Distribution:** There shall be no changes in the overall Budget Outlay of the PLI Scheme for Large Scale Electronics

Manufacturing as notified on 01.04.2020. With reference to Para 8.1 of the PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing notified on 01.04.2021, the Annual Incentive Outlay shall be revised as follows while keeping the overall incentive outlay for the scheme the same as approved by Union Cabinet on 20.03.2020:

Financial Year	Annual Incentive Outlay	Revised Incentive Outlay*
		<i>INR Crore</i>
FY 2021-22	5,334	900
FY 2022-23	8,064	4,578
FY 2023-24	8,425	6,504
FY 2024-25	11,488	8,674
FY 2025-26	7,640	10,192
FY 2026-27		7,753
<b>TOTAL</b>	<b>40,951</b>	<b>38,601</b>

**\*Note:** The budget outlay of INR 2,350 crore has been utilized for the Production Linked Scheme (PLI) for IT Hardware.

3. In view of the aforesaid revisions, **Annexure A** of the PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing dated 01.04.2020 shall be read as **Annexure-1** of this Notification.

Further, for the purpose of Second Round of PLI Scheme, **Para 2.3** of the *Supplementary Guidelines on Second Round of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 11<sup>th</sup> March 2021* shall be read as **Annexure-2** of this Notification.

4. The Base Year for the purpose of the PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing shall remain the same, i.e. Financial Year 2019-20, for computation of incremental investment and incremental sales of manufactured goods (as distinct from traded goods).

5. This Notification shall be read along with all the referred documents in this Notification incorporating the changes wherever applicable.
6. This issues with the approval of Hon'ble Minister for Electronics and Information and Technology.



(Saurabh Gaur)

Joint Secretary to the Government of India

Ph: 011-24363071

Email: [saurabh.gaur@meity.gov.in](mailto:saurabh.gaur@meity.gov.in)

**Copy to:**

1. All Concerned Ministries / Departments of Government of India
2. All States / Union Territories
3. Cabinet Secretariat
4. PMO
5. NITI Aayog
6. Comptroller and Auditor General of India
7. SS&FA, Ministry of Electronics and Information Technology
8. Industry Associations
9. IFCI Ltd. – Project Management Agency for the PLI Scheme
10. Internal circulation



(Saurabh Gaur)

Joint Secretary to the Government of India

Tel No. 011-24363071

Email: [saurabh.gaur@meity.gov.in](mailto:saurabh.gaur@meity.gov.in)

## Annexure-1

**Eligibility Threshold Criteria for first round of PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing**

Segment	Proposed Incentive Rate	Incremental Investment over Base Year	Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year
Mobile Phones (Invoice value of INR 15,000 and above) *		INR 1,000 Crore over 5 Years Cumulative Minimum as on: 31.03.2022: INR 250 Crore 31.03.2023: INR 500 Crore 31.03.2024: INR 750 Crore 31.03.2025: INR 1000 Crore	Year 1: INR 4,000 Crore Year 2: INR 8,000 Crore Year 3: INR 15,000 Crore Year 4: INR 20,000 Crore Year 5: INR 25,000 Crore
Mobile Phones (Domestic Companies) **	Year 1: 6% Year 2: 6% Year 3: 5% Year 4: 5% Year 5: 4%	INR 200 Crore over 5 Years Cumulative Minimum as on: 31.03.2022: INR 50 Crore 31.03.2023: INR 100 Crore 31.03.2024: INR 150 Crore 31.03.2025: INR 200 Crore	Year 1: INR 500 Crore Year 2: INR 1,000 Crore Year 3: INR 2,000 Crore Year 4: INR 3,500 Crore Year 5: INR 5,000 Crore
Specified Electronic Components		INR 100 Crore over 5 Years Cumulative Minimum as on: 31.03.2022: INR 25 Crore 31.03.2023: INR 50 Crore 31.03.2024: INR 75 Crore 31.03.2025: INR 100 Crore	Year 1: INR 100 Crore Year 2: INR 200 Crore Year 3: INR 300 Crore Year 4: INR 450 Crore Year 5: INR 600 Crore

**\*For eligibility all Incremental Sales of Manufactured Goods (covered under target segments) irrespective of Invoice Value shall be considered.**

**\*\*Domestic Companies shall be defined as those which are owned by resident Indian citizens as defined in the FDI Policy Circular of 2017. A company is considered as 'Owned' by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens**

## Annexure-2

**Eligibility Threshold Criteria for second round of PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing**

Segment	Proposed Incentive Rate	Incremental Investment over Base Year	Incremental Sales of Manufactured Goods over Base Year
Specified Electronic Components	Year 1: 5% Year 2: 4% Year 3: 4% Year 4: 3%	INR 25 Crore over 4 Years  Cumulative Minimum (Crore) at the end of: Year 1: INR 5 Crore Year 2: INR 11 Crore Year 3: INR 18 Crore Year 4: INR 25 Crore	Year 1: INR 15 Crore Year 2: INR 35 Crore Year 3: INR 60 Crore Year 4: INR 100 Crore

**File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part (1)**  
**Government of India**  
**Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)**  
**IPHW Division**

**Dated: 28.03.2023**

**Addendum**

**Amendments in Guidelines of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing**

**References**

- i. *PLI Scheme Notification No. CG-DL-E-01042020-218990 dated 01.04.2020 in Part – I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) [F.No. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*
- ii. *Guidelines for the Operation of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 1<sup>st</sup> June, 2020 [F.No. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*

Ministry of Electronics and Information Technology notified the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing on April 01, 2020. Subsequently, Guidelines for the operation of the Scheme were notified on 1<sup>st</sup> June, 2020.

2. As per Para 12.6 of the Scheme Guidelines, "the Empowered Committee will also be authorized to carry out any amendments in Scheme Guidelines". Therefore, in accordance with Para 12.6 of the Scheme, the EC in its meeting held on 14<sup>th</sup> March, 2023 has approved the following amendment in the PLI Scheme Guidelines:

<b>Para</b>	<b>Existing Para</b>	<b>Amended Para</b>
12.2	An applicant may submit a claim for disbursement of incentive as early as the end of the quarter in which the eligibility criteria for the year in consideration have been met. Claims	"An applicant may submit a claim for disbursement of incentive as early as the end of the quarter in which the eligibility criteria for the year in consideration have been met. Claims for disbursement of

for disbursement of incentive may be submitted only on a quarterly or half-yearly or annual basis. Claims for any period shall be made only once, unless withdrawn, and no subsequent part claims shall be allowed for the said period.	incentive may be submitted only on a quarterly or half-yearly or annual basis. Claims for any period shall be made only once, unless withdrawn, and no subsequent part claims shall be allowed for the said period, except, where any claim is deferred by PMA for accounting or regulatory rectification, such cases may be considered with subsequent incentive claim, for the period to which it pertains."
---	--

3. The PLI Scheme Guidelines issued on 1<sup>st</sup> June, 2020 shall be read incorporating the above changes wherever applicable.
4. This issues with the approval of Hon'ble Minister of Electronics and Information and Technology.

  
28/03/2023

**(Amitesh Kumar Sinha)**

**Joint Secretary to Government of India**

**Tel No. 011-24363078**

**Email: amitesh.iras@gov.in**

**File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part(1)**  
**Government of India**  
**Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)**  
**IPHW Division**

**Dated: 11<sup>th</sup> March, 2021**

**Supplementary Guidelines on Second Round of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing**

**References:**

- i. PLI Scheme Notification No. CG-DL-E-01042020-218990 dated 1<sup>st</sup> April 2020 in Part – I, Section 1 of the Gazette of India (Extraordinary) [F.No. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*
- ii. Guidelines for the Operation of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 1<sup>st</sup> June, 2020 [F.No. No. W-28/1/2019-IPHW-MeitY]*
- iii. Addendum: Amendments in Guidelines of Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing dated 11<sup>th</sup> March, 2021 [File No. W-28/1/2020-IPHW-MeitY-Part(1)]*

**1. Background**

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) notified the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Electronics Manufacturing on April 01, 2020. Subsequently, Guidelines for the operation of the Scheme were notified on 01.06.2020. The first round of the Scheme was open for receiving applications till 31.07.2020.

As per Para 6.2 of the PLI Scheme, *the Scheme may also be reopened for applications anytime during its tenure based on response from the Industry* and as per Para 12.5 of the Scheme, *the Empowered Committee (EC) may revise incentive rates, ceilings, target segments and eligibility criteria as deemed appropriate during the tenure of the Scheme*. Therefore, in accordance with the

abovementioned provisions, the EC in its meeting held on 11<sup>th</sup> February 2021 gave approval for the Second Round of the PLI Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing with the following revisions (Refer Para 2 below) in existing PLI Scheme Guidelines:

## 2. Revisions

2.1 For the purpose of Second Round of PLI Scheme, the following revisions have been done in the existing Scheme Guidelines. The revised Paras may be read as follows:

Para	Existing Scheme Guidelines	Revised Para in the Scheme Guidelines for Second Round
1.2	As per Para 6.1 of the Scheme, PLI will be open for receiving applications for four months from the date of notification. Since, the notification was published on 01-04-2020, applications will be received upto 31-07-2020.	In reference to Para 6.2 of the Scheme, the second round of PLI Scheme will be open for receiving applications until 31.03.2021.
2.1	<b>Target Segments:</b> In accordance with Para 4 of the Scheme, Target Segments shall mean two segments viz. Mobile phones and Specified Electronic Components as in Annexure B in the Scheme.	<b>Target Segment:</b> In accordance with Para 4 and Para 12.5 of the Scheme, the Target Segment shall mean <i>Specified Electronic Components</i> as in Annexure B of the Scheme.
2.4	<b>Application Window:</b> Time period allowed for filing of applications. In accordance with Para 6.1 of the Scheme, the Application Window shall be 4 months from the date of notification of the Scheme initially and may be extended and / or	<b>Application Window:</b> Time period allowed for filing of applications. The Application Window shall be open until 31.03.2021 initially and may be extended and / or reopened based on response from the industry.

	reopened based on response from the industry.	
2.16	<b>Incremental Investment:</b> Investment made in India after the end of the Base Year as defined.	<b>Incremental Investment:</b> Investment made in India after 31.03.2021.
3.4	For the purpose of determining eligibility of an applicant under the Scheme, in order to meet the threshold criteria of Incremental Investment for any year, the <b>cumulative value of investment done till such year</b> (including the year under consideration) over the Base Year shall be considered.	For the purpose of determining eligibility of an applicant with respect to Incremental Investment for any year, the <b>cumulative value of investment done till such year</b> (including the year under consideration) after 31.03.2021 shall be considered.
4.1.1	Investment as defined in Para 2.9 of these Guidelines shall be considered for determining eligibility under the Scheme provided such <b>Investment is made on or after 01.04.2020.</b>	Investment as defined in Para 2.9 of these Guidelines shall be considered for determining eligibility under the Scheme provided such <b>Investment is made on or after 01.04.2021.</b>
5.1	The Scheme shall be <b>open for applications till 31.07.2020</b> initially which may be extended.	The Scheme shall be <b>open for applications till 31.03.2021</b> which may be extended.
9.3	After the conclusion of initial round of applications, approvals will be granted to <b>not more than 5 eligible applicants in Target Segment Mobile Phones (Category – Invoice Value INR 15,000 and above); not more than 5 eligible applicants in Target Segment</b>	After the conclusion of Second Round of applications, approvals will be granted to <b>not more than 30 eligible applicants in the Target Segment.</b>

	<p><b>Mobile Phones (Category – Domestic Companies); and not more than 10 eligible applicants in Target Segment Specified Electronic Components.</b></p>	
<p><b>9.4</b></p>	<p>In case of receipt of eligible applications in excess of the limits specified above for any of the Target Segments, the eligible applications for the given Target Segment will be ranked from highest to lowest on the basis of consolidated global manufacturing revenue of the applicants (including its group companies), in the target segment, in the base year. <b>5 eligible applicants having the highest consolidated global manufacturing revenue in Target Segment Mobile (Category – Invoice Value INR 15,000 and above); 5 eligible applicants having the highest consolidated global manufacturing revenue in Target Segment Mobile (Category – Domestic Companies); and 10 eligible applicants having the highest consolidated global manufacturing revenue in Target Segment Specified Electronic Components;</b> shall be selected and granted approval under the Scheme.</p>	<p>In case of receipt of eligible applications in excess of the limits specified above for Target Segments, the eligible applications for the given Target Segment will be ranked from highest to lowest on the basis of consolidated global manufacturing revenue of the applicants (including its group companies), in the target segment, in the base year. <b>30 eligible applicants having the highest consolidated global manufacturing revenue in the Target Segment, in the base year,</b> shall be selected and granted approval under the Scheme.</p>

<b>10.2</b>	<p>The period for determination of baseline shall be as follows:</p> <p>10.2.1 Baseline for Investment: As on 31.03.2020</p> <p>10.2.2 Baseline for Sales of Manufactured Goods</p> <p>a) First year i.e., FY 2020-21: Period from 01.08.2019 to 31.03.2020</p> <p>b) Second year onwards: Period from 01.04.2019 to 31.03.2020</p>	<p>The period for determination of baseline shall be as follows:</p> <p>10.2.1 Baseline for Investment: As on 31.03.2021</p> <p>10.2.2 Baseline for Net Sales of Manufactured Goods (covered under the Target Segment): Period from 01.04.2019 to 31.03.2020</p>
<b>10.6</b>	10.6.7 Baseline for Investment (as on 31.03.2020)	10.6.7 Baseline for Investment (as on 31.03.2021)

**2.2 For the purpose of Second Round of PLI Scheme, Annexure 1 of the Scheme Guidelines shall be read as follows:**

**Target Segments Eligible under PLI**

<b>S. No.</b>	<b>Description of Goods</b>
1	<b>Specified Electronic Components</b>
1.1	SMT components
1.2	Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, thyristors, etc.
1.3	Passive components including resistors, capacitors, etc. for electronic applications
1.4	Printed Circuit Boards (PCB), PCB laminates, prepregs, photopolymer films, PCB printing inks

1.5	Sensors, transducers, actuators, crystals for electronic applications
1.6	System in Package (SIP)
1.7	Micro / Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
1.8	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

**2.3 For the purpose of Second Round of PLI Scheme, Annexure 2 of the Scheme Guidelines shall be read as follows:**

**Eligibility Threshold Criteria**

<b>Target Segment</b>	<b>Incentive Rate</b> (on Incremental Sales of Manufactured Goods)	<b>Incremental Investment</b>	<b>Incremental Sales of Manufactured Goods</b>
Specified Electronic Components (detailed in <b>Annexure 1</b> )	Year 1: 5% Year 2: 4% Year 3: 4% Year 4: 3%	INR 25 crore over 4 Years Cumulative Minimum: Year 1: INR 5 crore Year 2: INR 11 crore Year 3: INR 18 crore Year 4: INR 25 crore	Year 1: INR 15 crore Year 2: INR 35 crore Year 3: INR 60 crore Year 4: INR 100 crore

*Year 1: FY 2021-22; Year 2: FY 2022-23; Year 3: FY 2023-24; Year 4: FY 2024-25*

3. Incentives under Second Round of PLI Scheme shall be applicable from 01.04.2021.
4. Applicant companies approved under the First Round of the PLI Scheme shall not be allowed to apply under the Second Round of PLI Scheme. However, group companies having minority or non-controlling interest in applicant companies approved under Round 1 shall not be restricted from applying under Round 2 of the Scheme.
5. These Supplementary Guidelines shall be read along with the PLI Scheme Guidelines issued on 01.06.2020 and Addendum dated 11<sup>th</sup> March, 2021 incorporating the changes wherever applicable.
6. This issues with the approval of Hon'ble Minister for Electronics and Information and Technology.

*Saurabh Gaur*

**(Saurabh Gaur)**

**Joint Secretary to the Government of India**

**Tel No. 011-24363071**

**Email: [saurabh.gaur@meity.gov.in](mailto:saurabh.gaur@meity.gov.in)**